RAJYA SABHA

Thursday, the 30th July, 1992/8 Sravana, 1914 (Saka)

The House met at eleven of the clock, **The Deputy Chairman** in the Chair.

SHRI DIPEN GHOSH: Madam, have you noticed that Shrimati Jayanthi Natarajan joined this side?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Never, never.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let her come to me. Then I will take a decision. Not on the floor of the House. Maybe, she is influencing the Opposition.

SHRI MENTAY PADMANABHAM: She is trying to entice the Opposition to that side.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: She has already influenced.

THE DEPUTY CHAIRMAN: In this House, influence is more necessary than enticing.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Setting up of international sub-contracting exchange

*321 SHRI SATISH PRADHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up an international sub-contracting exchange as reported in the *Indian Express* dated the 9th July, 1992;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the benefits likely to accrue from the project, total cost, participation of international organisations and time schedule for completion thereof together with the details of MOU signed in this regard?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो ने एशिया में औद्योगिक उप-ठेकाएक्सचेंजों का उप-क्षेत्रीय नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव किया है । इस प्रस्ताव का उद्देश्य एक उप-क्षेत्रिय उप-ठेका पद्धति तथा नेटवर्क के माध्यम से औद्योगिक उप-ठेका क्षमताओं तथा अवसरों के संबंध में तकनीकी एवं आर्थिक सूचना का आदान-प्रदान करने हेतु भागीदार देशों को समर्थ बनाना है ।

(ग) इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

उपसभापति : आप अपना पहला सवाल रखिये ।

SHRI SATISH PRADHAN: Since such networks are already operating in Latin American and Arabian regions, may I ask the hon. Minister to explain as to how these networks are functioning? Have some modifications been carried out in the MOU in the light of the experience of the networks operating and what are the details thereof?

श्रीमती कृष्णा साही : उपसभापति महोदया, सब से पहले मैं माननीय सदस्य से कहना चाहती हूं कि इनका जो प्रश्न है वह इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के आधार पर है । परन्तु वस्तु-स्थिति से बिलकुल भिन्न है । जो इण्डियन एक्सप्रेस में आया है, उसके आधार पर माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है–

"The Ministry of Industry is setting up an International Sub-contracting Exchange in India in collabortaion with UNIDO."

यह मात्र एक प्रस्ताव ही है । दूसरा है कि–

"The project will be finalised in the next two months."

अभी इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है । तीसरा है—

"The project would include India, Bangladesd, Sri Lanka, Mauritius, Indonesia and the Philippines."

इण्डिया, बंगलादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया और केवल फिलिपींस ही मारिशयस नहीं है ।

"At the moment, India has about seven sub-contracting exchanges functioning under the Ministry of Industry."

यह सब इण्डियन एक्सप्रेस का है । इसके उत्तर में मैं इनको बताना चाहती हूं कि

"In fact, 16 Sub-contracting Exchanges are operating in the country under the

Development Commissioner of Small-Scale Industries."

उपसभापति : यह नहीं पूछ रहे हैं कि इण्डियन एक्सप्रेस ने क्या लिखा । That is not the issue.

वे यह पूछ रहे है कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं यूनिडो की प्रोपोजल . . . .

श्रीमती कृष्णा साही : अभी तो प्रस्ताव विचाराधीन है । मैंने उत्तर में कहा है कि सरकार (व्यवधान)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: It is the maiden reply of the Minister.

SHRI MENTAY PADMANABHAM: It is her maiden reply, Madam.

SHRI DIPEN GHOSH: Maiden question, maiden answer.

श्रीमती कृष्णा साही : उपसभापति महोदया, . . . (व्यवधान)

उपसभापति : जवाब तो सुनिये ।

श्रीमती कृष्णा साही : मैंने अपने उत्तर में कहा है कि भारत सरकार यूनिडो की मदद से एक सवकंट्रेक्टिंग एक्सचेंज स्थापित करने का इरादा रखती है लेकिन यह प्रस्ताव विचाराधीन है ।

उपसभापति : यह विचाराधीन है अभी ।

श्रीमती कृष्णा साही : सरकार सभी बिन्दुओं पर विचार करके ही कुछ करेगी ।

SHRI SATISH PRADHAN: Madam, I would like to know whether the Government is going to take sufficient precaution in signing the MOU so that the developed countries do not exploit the developing countries.

श्रीमती कृष्णा साही : उपसभापति महोदया, जब प्रस्ताव ही विचाराधीन है तो एम.ओ.यू. का प्रश्न ही नहीं उठता है । अभी तो प्रोजेक्ट की स्वीकृति नहीं दी गयी है । एम.ओ.यू. का प्रश्न तो प्रोजेक्ट की स्वीकृति के बाद ही उठेगा ।

श्री प्रमोद महाजन : लेकिन प्रिवेंशन ले सकते है, यह तो बता सकती हैं । उन्होंने इतना ही पूछा है कि आप प्रिवेंशन लेंगी ? इसमें हां कह सकती है ।

श्रीमती कृष्णा साही : सरकार सब दृष्टिकोण से विचार करके ही कुछ करेगी ।

Generation of power through Thermal ocean Energy Conversion

*322. DR. NAUNIHAL SINGH:
SHRI SOM PAL:†

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether technology is available for generating power through thermal ocean energy conversion;

(b) whether some study has been made to evaluate the feasibility and total potential of such generation in India;

(c) if so, what are the details thereof;

(d) whether any offer or proposal for the purpose has been received by Government; and

(e) if so, what are the details thereof; and what action is being taken to tap this new-source of energy?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI SUKH RAM): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

Technology for generating power through Ocean Thermal Engery Conversion (OTEC) is not available in India. According to information available, OTEC technology is at an experimental stage in USA and Japan. It is yet to be demonstrated in Megawatt Range.

†The question was actually asked in the floor of the House by Shri Som Pal.